



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

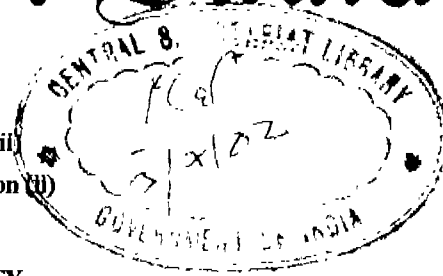
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 74]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 22, 2002/माघ 2, 1923

No. 74]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 22, 2002/MAGHA 2, 1923

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2002

का.आ. 90(अ).— केन्द्रीय सरकार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949(1949 का 10) की धारा 45 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस धारा की उपधारा (1)के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए आवेदन पर विचार करने के पश्चात् बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड की बाबत 22 जनवरी, 2002 को कारबार की समाप्ति से तारीख 21 अप्रैल, 2002 तक, जिसके अंतर्गत यह तारीख भी है, की कालावधि के लिए अधिस्थगन आदेश करती है और एतद्वारा अधिस्थगन की कालावधि के दौरान उस बैंककारी कंपनी के विरुद्ध सभी कार्रवाईयों और कार्यवाइयों को प्रारम्भ करने या चालू रखने को इस शर्त के अधीन रहते हुए स्थगित करती है कि ऐसे स्थगन से उक्त अधिस्थगन की धारा 35 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा उसकी शक्तियों के प्रयोग पर या उक्त अधिनियम की धारा 38 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उसकी शक्तियों के प्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

2. केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह भी निदेश देती है कि बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड को मंजूर की गयी अधिस्थगन की कालावधि के दौरान, वह बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुज्ञा के बिना --

(क) अपने दायित्वों और बाध्यताओं के निर्वहन में या अन्यथा कोई उधार या अग्रिम नहीं देगा, कोई दायित्व उपगत नहीं करेगा, कोई विनिधान नहीं करेगा या किसी संदाय के लिए करार या उसका

संवितरण नहीं करेगा या इसमें इसके पश्चात उपबंधित विस्तार और रीति के सिवाय कोई समझौता या ठहराव नहीं करेगा :-

(I) प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते में या किसी अन्य निक्षेप में, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, कुल अतिशेष के 2500 रु० से अनधिक राशि, परन्तु यह तब, जब कि ऐसी कोई रकम ऐसे किसी निक्षेपकर्ता को जो किसी रूप में बैंक का ऋणी है, संदत्त नहीं की जाएगी ।

(II) कोई ऐसा व्यय, जो उक्त बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध फाइल किए गए किसी वाद या अपील के संबंध में या बैंक द्वारा अभिप्राप्त डिक्री के संबंध में या उसको देय किसी रकम को वसूल करने के लिए आवश्यक रूप से उपगत किया जाता है, परन्तु यदि ऐसे प्रत्येक वाद या अपील या डिक्री या कार्यवाही की बाबत व्यय 2500 रु० से अधिक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुज्ञा उपगत किए जाने से पूर्व अधिप्राप्त की जाएगी ।

(III) किसी अन्य मद पर कोई अन्य व्यय, जहां तक वह बैंककारी कंपनी के प्रतिदिन के प्रशासन का संचालन करने के लिए बैंककारी कंपनी की राय में आवश्यक है, परन्तु जहां किसी कैलेंडर मास में किसी मद पर कुल व्यय, अधिस्थगन के आदेश के पूर्व छह कैलेंडर मास के दौरान उस मद के मद्दे औसत मासिक व्यय से अधिक है या जहां विगत में उस मद के मद्दे कोई व्यय उपगत नहीं हुआ है और ऐसे में मद पर व्यय 2500 रु० से अधिक है, यहां भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुज्ञा अतिरिक्त व्यय उपगत किए जाने के पूर्व अधिप्राप्त की जाएगी ।

(IV) उक्त बैंक द्वारा जारी किए गए किसी ड्राफ्ट या संदाय आदेशों की रकम और जो उस तारीख को जिसको अधिस्थगन आदेश प्रवृत्त होता है, असंदत्त रह जाती है ; और

(V) तारीख 22 जनवरी, 2002 को या उससे पूर्व संग्रहण के लिए प्राप्त और उस तारीख के पूर्व उस तारीख में या उसके पश्चात वसूल किए गए बिलों की रकम ।

(ख) अपनी स्थावर संपत्ति का विक्रय, अंतरण या उसका अन्यथा व्यय नहीं करेगा ।

3. केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह भी निदेश देती है कि बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड उसे मंजूर की गयी स्थगन की कालावधि के दौरान निम्नलिखित और संदाय, अर्थात् बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड, को भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या इसके किसी समनुषंगी या किसी अन्य बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों या अन्य प्रतिभूतियों के विरुद्ध उधारों या अग्रिमों के प्रतिदाय के लिए मंजूर की गयी राशियों और जो उस तारीख को जिसको अधिस्थगन आदेश प्रवृत्त होता है, असंदत्त है, कर सकता है ।

4. केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा यह और निदेश देती है कि अधिस्थगन की कालावधि के दौरान बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड, पूर्वोक्त संदाय करने के प्रयोजन के लिये भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य बैंक के पास अपना खाता चलाने के लिए अनुज्ञात होगा, परन्तु इस आदेश किसी अन्य पूर्वोक्त बैंक से अपना यह समाधान करने की अपेक्षा करती है कि इस आदेश द्वारा अधिरोपित शर्तों का बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड के पक्ष में कोई रकम जारी किए जाने से पूर्व पालन किया जा रहा है ।

5. केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह और निदेश देती है कि बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड , अधिस्थगन की कालावधि के दौरान, ऐसे किन्हीं बिलों को, जिनकी वसूली नहीं हुई है, उसको प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति को, उस व्यक्ति द्वारा इस निमित्त किए गए अनुरोध पर उस दशा में वापस लौटा सकेगा यदि बैंक को ऐसे बिलों में कोई अधिकार या हक या हित नहीं है ।

6. केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह भी निदेश देती है कि बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड , ऐसे माल या प्रतिभूतियों को निर्मुक्त या परिदत्त कर सकेगा जो किसी उधार, नकद प्रत्यय या ओवरड्राफ्ट के लिए इसके पास गिरवी रखा गया है, आडमानित या बंधक या अन्यथा प्रभारित किया गया है :-

(I) किसी ऐसी दशा में जिसमें, यथास्थिति, उधार लेने वाले या उधार लेने वालों से देय सभी रकमों के मद्दे पूर्ण संदाय बैंक द्वारा बिना शर्त के प्राप्त कर लिया गया है ; और

(II) किसी अन्य दशा में, अनुबंधित अनुपातों या ऐसे अनुपातों , जो अधिस्थगन आदेश के प्रवृत्त होने से पूर्व रखे गए थे, इन दोनों में से जो भी उच्चतर हो, से नीचे उक्त माल या प्रतिभूतियों पर सीमाओं के अनुपात को कम किए बिना ऐसी मात्रा तक जो आवश्यक या संभव हो ।

[फा. सं. 15/2/2000-बीओए

शेखर अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2002

S.O. 90(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, after considering an application made by the Reserve Bank of India under Sub-section (1) of that Section hereby makes an Order of Moratorium in respect of the Benares State Bank Ltd., for the period from the close of business on the 22nd January, 2002 upto and inclusive of the 21st April, 2002 and hereby stays the commencement or continuance of all actions and proceedings against that banking company during the period of moratorium, subject to the condition that such stay shall not in any manner prejudice the exercise by the Central Government of its powers under clause (b) of Sub-section (4) of Section 35 of the said Act or the exercise by the Reserve Bank of India of its powers under Section 38 of the said Act.

2. The Central Government hereby also directs that during the period of moratorium, the Benares State Bank Ltd., shall not, without the permission in writing of the Reserve Bank of India-

(a) grant any loan or advance, incur any liability, make any investment or agree to or disburse any payment, whether in discharge of its liabilities and obligations or otherwise, or enter into any compromise or arrangement, except to the extent and in the manner provided hereunder:

(i) payment of a sum not exceeding Rs.2,500/- of the total balance in every savings bank or current account or any other deposit by whatever name called, provided that no amount shall be paid to any depositor who is indebted to the bank in any way;

(ii) incurring expenditure which has necessarily to be incurred in connection with any suits or appeals filed by or against or decrees obtained by the said bank or for realising any amounts due to it, provided that if the expenditure in respect of each such suit or appeal or decree or proceeding is in excess of Rs.2,500/-, the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before it is incurred;

(iii) incurring expenditure on any other item in so far as it is in the opinion of the banking company necessary for carrying on the day-to-day administration of the banking company, provided that where the total expenditure on any item in any calendar month exceeds the average monthly expenditure on account of that item during the six calendar months preceding the Order of Moratorium, or if no expenditure has been incurred on account of that item in the past exceeds a sum of Rs.2,500/-, the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before the additional expenditure is incurred;

(iv) payment of the amounts of any drafts or pay Orders issued by the said bank and remaining unpaid on the date on which the Order of Moratorium comes into force; and

(v) the amounts of the bills received for collection on or before the 22nd January, 2002 and realised before, on or after that date.

(b) sell, transfer or otherwise dispose of any of its immovable properties.

3. The Central Government hereby also directs that the Benares State Bank Ltd., may, during the period of the moratorium granted to it, make the following further payments, namely, the amounts for repaying loans or advances granted against Government securities or other securities, to the Benares State Bank Ltd., by the Reserve Bank of India or the State Bank of India or any of its subsidiaries or by any other bank and remaining unpaid on the date on which the Order of Moratorium comes into force.

4. The Central Government hereby further directs that during the period of moratorium the Benares State Bank Ltd., shall be permitted to operate its accounts with the Reserve Bank of India or with any other bank for the purpose of making the payments aforesaid, provided that nothing in this Order shall be deemed to require the Reserve Bank of India or any other bank aforesaid to satisfy itself that the conditions imposed by this Order are being observed before any amounts are released in favour of the Benares Bank Ltd.

5. The Central Government hereby further directs that the Benares State Bank Ltd., may, during the period of moratorium, return any bills which have remained unrealised to the persons entitled to receive them on a request being made in this behalf by such persons, if the bank has no right or title to, or interest in, such bills.

6. The Central Government hereby also directs that the Benares State Bank Ltd., may, release or deliver goods or securities which have been pledged, hypothecated or mortgaged or otherwise charged to it against any loan, cash credit or overdraft:

- (i) in any case in which full payment towards all the amounts due from the borrower or borrowers, as the case may be, has been received by the bank, unconditionally, and
- (ii) in any other case, to such an extent as may be necessary or possible, without reducing the proportions of the margins on the said goods or securities below the stipulated proportions or the proportions which were maintained before the Order of moratorium came into force, whichever may be higher.

[F.No. 15/2/2000-BOA]

SHEKHAR AGARWAL, Jt. Secy.

